''राइट टू हैल्थ'' एक्ट पर विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में घमासान

सरकार का कहना था कि मौजूदा योजनाओं में स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अलग कानून की जरूरत नहीं

■ **कांग्रेस का कहना था कि नियम नहीं बना कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।**

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने, अप्रैल 2023 में अधिसूचित राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय हुआ और इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस और सरकार के जवाब की जानकारी भी मांगी।

इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से ठीक पहले बिना पर्याप्त तैयारी के यह अधिनियम लेकर आई थी। नियम नहीं बनाए गए और हितधारकों से समुचित चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम के नियमों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और निर्णय प्रतीक्षित है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही ''मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना'' के तहत 25 लाख रुपये तक का वार्षिक कैशलैस इलाज उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत1.36 करोड़ पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और 2179 उपचार पैकेज इसमें शामिल हैं। नि:शुल्क जांच, दवाइयां, ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं, हीमोडायलिसिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहले से दी जा रही हैं। ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि स्थिति नहीं संभली तो सदन स्थगित करना पड़ेगा। अंततः विपक्ष ने विरोधस्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।

मोदी आज नए ऑफिस 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होंगे

■ **सेवा तीर्थ के साथ ही कर्त्तव्य भवन-1 और 2 का भी शाम 6 बजे उद्घाटन होगा।**

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होंगे। जानकारी के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे 'सेवा तीर्थ' बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है।

तालेड़ा के स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका पर हमला किया

बालिका के दादा के अनुसार, उसके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर घाव हैं

■ **कोटा मैडिकल कॉलेज में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि बालिका के शरीर पर करीब 20 घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में घाव हो गया, इसलिए श्वसन तंत्र को सुचारु रखने के लिए ट्यूब डाली गई है।**

कोटा, 12 फरवरी (निसं)। बूंदी जिले के तालेड़ा में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में गुरुवार को बालिका तृप्ति सेन पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके शरीर पर कई जख्म हो गए हैं। घटना के बाद बालिका को पहले तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के इमरजैंसी आई.सी.यू. में भर्ती किया गया।

स्कूल के प्रिंसिपल गोवर्धन गोपाल का कहना है कि बच्चे लंच के समय भोजन करने के बाद मैदान में खेल रहे थे। इसी दौरान 3 - 4 कुत्तों ने बालिका पर हमला कर दिया था। इन डॉग्स को भगाकर केयरटेकर ने बड़ी मुश्किल से बालिका को बचाया है। इसके बाद तत्काल बालिका को अस्पताल लेकर गए, जहां से बच्ची को कोटा रेफर किया गया है।

बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं। वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा है कि उसके शरीर पर चेहरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले। मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज का कहना है कि बालिका के शरीर पर करीब 20 के आसपास घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है। इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारू रखा जा सके। बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित, कई जगह पर घाव के निशान हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है और ट्रेलर तथा प्रचार सामग्री पहले ही वापस ले ली गई है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी बताने को कहा कि क्या फिल्म ''घूसखोर पंडित'' में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है।

कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है।

अदालत ने, ''फ्राईडे फिल्मवर्क्स'' द्वारा निर्मित इस फिल्म की टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि फिल्म निर्माता संयम क्यों नहीं बरत सकते। कोर्ट ने कहा, ''जब समाज में पहले से ही विभाजन है, तो किसी समाज के एक वर्ग को बदनाम क्यों किया जाना चाहिए?''

'वोकिज़्म' को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे फिल्म शीर्षक समाज में अशांति पैदा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाईचारा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे सीमित नहीं कर सकती।

''घूसखोर पंडित'' विवाद में तब आई, जब 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स इंडिया के 2026 लॉन्च कार्यक्रम में इसका शीर्षक और टीजर सामने आया।

बेअसर रहा भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की सभी ट्रेड यूनियनें, किसान और मजदूर मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं।

ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित, कई राज्यों में मिला-जुला असर देखने को मिला।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज़ किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों ने आज दिनभर की हड़ताल कर केन्द्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मंच ने दावा किया कि नई श्रम संहिताओं सहित, अन्य मुद्दों के विरोध में सामान्य हड़ताल के लिए 30 करोड़ मजदूरों को संगठित किया जा रहा है।

कक्षा-10 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षा 2026 के लिए बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें प्रश्नपत्र प्रारूप में संशोधन और वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था शामिल है।

विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्रों में अब स्पष्टता और मूल्यांकन मानकों में सुधार के लिए नए खंडीय प्रारूप (सैक्शनल फॉर्मेट) का पालन किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी।

इस प्रणाली के तहत, विद्यार्थियों को अपने अंक सुधारने या जिन विषयों में वे फेल हुए है उन्हें पास करने के लिए दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इस योजना के अनुसार, छात्र दूसरी परीक्षा में अधिकतम तीन विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं, जो 15 मई से 1 जून 2026 तक होनी है।

सीबीएसई की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षाएं 2026, 17 फरवरी से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं भारत और विदेश के 26 देशों में स्थित 31,000 से अधिक संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10 की परीक्षा में सबसे पहले गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) विषय का पेपर होगा।

'दिल्ली हवा खाने नहीं आए हैं, राजनीति करने आए हैं'

कर्नाटक के नेता शिवकुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की

■ **डी के शिवकुमार ने खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की।**

■ **शिवकुमार की इस मीटिंग के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरु हो गई है।**

नई दिल्ली, 12 फरवरी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं से गुरुवार को यहां अलग-अलग मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवकुमार ने कहा कि वे यहां सिर्फ दिल्ली की हवा खाने नहीं आए हैं, बल्कि राजनीति करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय ही हर सवाल का जवाब देगा।

सोनिया गांधी से दस जनपथ स्थित आवास पर मुलाकात के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि वे सड़क पर खड़े होकर राजनीति नहीं करना चाहते और पार्टी नेतृत्व से सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की जानकारी दी। शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली आने पर पार्टी नेतृत्व को सभी मामलों की जानकारी देनी होती है, जिस पर विस्तार से बातचीत हुई।

हालांकि शिवकुमार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात पर सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व को लेकर खींचतान पिछले साल नवंबर से जारी है, जब सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंची थी।

'दूषित फल-सब्जियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि डेयरियों में पहुंचा हुआ दूध मिलावटी नही है। इस दौरान पूर्व महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि पशुओं को ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है, लेकिन इस इंजेक्शन के असर से दूध दूषित हो जाता है। इस पर अदालत ने आर.सी.डी.एफ. को पक्षकार बनाते हुए इस पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को रखी है।

भारत में निपाह वायरस से पहली मौत

■ **दो संक्रमित मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा था। मेल नर्स ठीक हो गया, महिला नर्स की मृत्यु हो गई।**

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दो मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इस साल निपाह वायरस से यह पहली मौत है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 11 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए निपाह संक्रमण के दो पॉजिटिव मामलों में से एक नर्स थीं, जो गंभीर रूप से बीमार थीं और अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल के तहत भर्ती थीं। 25 साल की महिला नर्स का बुधवार को उपचार के दौरान हृदयगति रुकने से निधन हो गया।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उन्हें आईसीयू में विशेषज्ञ निगरानी में रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक प्रोटोकॉल के तहत संपर्क में आए लोगों की निगरानी और अन्य एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दोनों संक्रमित नर्सिंग स्टाफ नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल थीं। पुरुष नर्स इलाज के दौरान ठीक हो गया, लेकिन महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महिलाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं प्रमुख दलों ने भी उन्हें केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नामांकन दिए हैं। 2026 के चुनाव महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट और जबरदस्त गिरावट दर्शाते हैं और बांग्लादेश की राजनीति में लैंगिक समानता के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुरुवार को चुनाव के दिन ढाका में भारी मतदान देखा गया, जहां जमात और बीएनपी के बीच मुकाबला चुनावी परिदृश्य को परिभाषित करता नज़र आया। जनरेशन-ज़ैड आंदोलन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आईं।

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के स्थगन के बाद केन्द्र सरकार से मंजूरी पाने वाली पहली बड़ी नई परियोजना है। इसके अलावा, पाकल डुल, किरू और रतले बांध परियोजनाओं को भी शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पानी के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन होगा और देश की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

पाकिस्तान भारत की इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा बांध बनाने से पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु नदी के साझा पानी के प्रवाह पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे उसके देश के अस्तित्व से जुड़ा जल अधिकार प्रभावित होगा।

भारत द्वारा चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की सावलकोट जलविद्युत परियोजना पर काम शुरू करने की खबरों के बाद पाकिस्तान सरकार ने सिंधु वॉटर्स कमिश्नर के स्तर पर चिंता जताई है और इस परियोजना से जुड़ी जानकारी और बातचीत की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, ''सिंधु जल संधि एक ''बाइंडिंग इन्टरनैशनल इन्स्ट्रूमैंट'' (बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता) है और कोई भी एकतरफा कदम या अवहेलना इस कानूनी स्थिति को नहीं बदल सकती। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाइयों को चुनौती देगा, क्योंकि देश के लगभग तीन चौथाई पानी का स्रोत चिनाब जैसी पश्चिमी नदियां हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ विवादों और मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के जरिए करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कायदे, कानून व प्रक्रिया ...

■ **''डिस्क्वालिफिकेशन'' करने के लिए कायदे-कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी का न होना, फिर कारण बना, राहुल गांधी को ''डिस्क्वालिफाई'' करने के प्रयास के असफल होने का।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे फर्जी ही कहा जा सकता है।

लेकिन सरकार की हर बात को दोहराने वाला सुविधाजनक गोदी मीडिया यह खबर चला रहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

यह बात निश्चित रूप से हर उस भाजपा समर्थक के दिल और दिमाग में हो सकती है जो राहुल गांधी से नफरत करता है, और ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। लेकिन बिना सही नियम और प्रक्रिया के यह सपना हकीकत कैसे बनेगा? यही वह मुख्य सवाल है, जिसे पूछा जाना चाहिए।

'संविधान के अनुरुप है एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव'

■ **पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने प्रस्ताव को लेकर गठित जेपीसी की मीटिंग में कहा**

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी। ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की गुरुवार को हुई बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रस्ताव संविधान के अनुरूप है और यह मूल ढ ांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और यह उसका विशेषाधिकार है। इसमें लोकतंत्र या संघीय ढ ांचे का कोई उल्लंघन नहीं है।

बैठक के बाद संसद के बाहर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी दी कि बैठक में सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। पूर्व न्यायमूर्ति बीआर गवई ने बैठक में आकर सदस्यों द्वारा संवैधानिक वैधता से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा सभी दलों को राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए, ताकि विश्व के सामने देश की एकता प्रदर्शित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनावी सुधारों को लागू किया जाता है तो पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी और एक देश एक चुनाव कराने का समर्थन किया। इसके बाद इस विधेयक को 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। विधेयक को 19 दिसंबर 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

श्रीलंका के लिए हवाई उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि

भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलम्बो में होने वाले मुकाबले के कारण यह वृद्धि हुई है

■ **बड़ी संख्या में लोग कोलम्बो जा रहे है इस वजह से चेन्नई से कोलम्बो की हवाई टिकट, जो 7,127 रुपए की होती थी, के दाम बढ़कर 22 से 25 हजार तक पहुँच गए हैं।**

चेन्नई, 12 फरवरी। श्रीलंका में 15 फरवरी को टी-20 विश्व कप का भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चेन्नई से श्रीलंका जाने के टिकट बुक कर रहे हैं। इस कारण चेन्नई से श्रीलंका जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है।

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रतिदिन श्रीलंका के लिए 8 उड़ानें और श्रीलंका से चेन्नई के लिए 8 उड़ानें संचालित होती हैं, यानी कुल 16 उड़ान सेवाएं चलती हैं।

इसके अलावा, श्रीलंका के रास्ते कई अन्य देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स उपलब्ध होने के कारण किराया सामान्यतः कम रहता है। इसी वजह से चेन्नई से श्रीलंका जाने वाले यात्रियों की संख्या आमतौर पर अधिक रहती है।

सामान्य दिनों में चेन्नई-श्रीलंका के बीच हवाई किराया लगभग 7,127 रुपये होता है, लेकिन 13 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास का किराया 22,073 रुपये से 25,207 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 42,231 रुपये तक हो गया है।

14 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस का किराया 20,708 रुपये से 25,207 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 35,217 रुपये तक बढ़ गया है। मैच के दिन यानी, 15 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस में किराया 18,283 रुपये से 19,464 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस में 28,660 रुपये से 42,231 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था कि गांधी के बयानों से संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुई है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, और संसदीय संदर्भ में यह एक गंभीर आरोप है।

लेकिन शाम तक परिदृश्य बदलता दिखाई दिया। संसदीय सूत्रों ने संकेत दिया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने, या अयोग्यता से संबंधित किसी प्रस्ताव को संस्थागत समर्थन नहीं मिला। संसदीय कार्यसूची में किसी औपचारिक उल्लेख का न होना इस बात का संकेत था कि इस कदम पर पुनर्विचार किया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली होने के बावजूद, भाजपा के पास वर्तमान लोकसभा में ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ विवादास्पद अनुशासनात्मक कार्रवाई आसानी से की जा सके। ऐसे किसी भी कदम के लिए, सदन प्रबंधन, सहयोगियों के साथ समन्वय और, सबसे ऊपर, संभावित प्रतिक्रिया का राजनीतिक आकलन आवश्यक होता।

एनडीए के व्यापक दायरे के सूत्रों के अनुसार, टीडीपी और जेडी (यू) जैसे प्रमुख सहयोगी दल ऐसे बड़े टकराव से असहज हो सकते हैं, क्योंकि इसे असहमति दबाने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं चुनावों को देखते हुए, गठबंधन का गणित, वैचारिक स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी अतिशयता पूर्ण कार्रवाई से विपक्ष को एकजुट होने का अवसर मिल सकता था और इस कार्रवाई से गांधी की राष्ट्रीय छवि के और मजबूत हो जाने की सम्भावना थी।

इसके अतिरिक्त, इस पूरे घटनाक्रम में छवि-प्रबंधन का पहलू भी महत्वपूर्ण है। किसी भाषण के हिस्सों को हटाना अध्यक्ष का एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, लेकिन जब यह कदम विवादास्पद राजनीतिक आरोपों से जुड़ता है, तो कभी-कभी वही बात और अधिक फैल जाती है, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है।

डिजिटल युग में, अभिलेखों से हटाए गए अंश अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, जिससे सेंसरशिप का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े संभावित भविष्य के खुलासों से सम्बन्धित अटकलों ने राजनीतिक माहौल में अनिश्चितता का तत्व जोड़ दिया है। यद्यपि शीर्ष भारतीय नेतृत्व को फंसाने वाले किसी संभावित खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों का प्रसार ही राजनीतिक हलकों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे माहौल में संसदीय टकराव को बढ़ाना अनिश्चित परिणामों वाला दु:साहस माना जा सकता था।

मोदी सरकार के सामने दृढ़ता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि या स्पष्ट संवैधानिक आधार के, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता समाप्त करने के सीधे प्रयास को न केवल प्रक्रियात्मक और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता, बल्कि लोकतन्त्र को कमज़ोर करने के विपक्षी दलों के आरोपों को भी बल मिल सकता था।

राहुल गांधी के लिए यह प्रकरण उनके विकसित होते संसदीय व्यक्तित्व को रेखांकित करता है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो तीखे टकराव से पीछे नहीं हटते। यह रणनीति उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ देगी या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। फिलहाल, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आसन्न प्रतीत हो रहा था, वह राजनीतिक दांव-पेंच और संसदीय व्यावहारिकता के टकराव का उदाहरण बन गया है।

निष्कर्षत:, यह प्रकरण समकालीन भारतीय राजनीति की इस व्यापक सच्चाई को उजागर करता है कि लड़ाइयाँ केवल सदन के पटल पर ही नहीं, बल्कि धारणा, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी गणित के क्षेत्र में भी लड़ी जाती हैं और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कदम वही होता है, जो अंतत: उठाया ही नहीं जाता।

नार्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी बेटी को वारिस बनाया

प्योंगयांग, 12 फरवरी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी जू-ऐ को अपना वारिस चुन लिया है। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी (एनआईएस) ने गुरुवार को देश के सांसदों के सामने यह दावा किया। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (एनआईएस) ने कहा कि उनके इस दावे के पीछे कई चीजों को आधार बनाया गया है। इनमें उत्तर कोरिया के सरकारी कार्यक्रमों में जू ऐ की बढ़ ती उपस्थिति एक अहम वजह है। इससे लगता है कि किम ने अपने वारिस पर फैसला ले लिया है। एनआईएस ने कहा है कि उनकी इस पर नजर होगी कि जू-ऐ इस महीने के आखिर में नॉर्थ कोरिया की पार्टी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं। यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट पांच साल में एक बार होता है। टीनएज जू-ऐ का इस कार्यक्रम में आना इस बात की तस्दीक होगी कि वे सत्ता संभालने वाली अपने परिवार की चौथी पीढ़ी बनने जा रही हैं।

हिंसा व हत्याओं के वातावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच वोटों के लिए मुकाबला हुआ। मतदान प्रक्रिया बीएनपी और जमात के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुईं।

पहले, शेख हसीना के शासनकाल में बीएनपी और जमात ने चुनाव लड़ने के लिए आपस में गठजोड़ किया था। पर अब अवामी लीग के मैदान में न होने से ये दोनों कट्टरपंथी दल अब एक-दूसरे से अलग हो गए हैं और सत्ता पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जमात एक इस्लामी झुकाव वाला बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है।

भारत के लिए ये दोनों दल एक तरह से ''हॉब्सन चॉइस'' प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दोनों ही मूल रूप से भारत-विरोधी हैं और दोनों ने देश में बचे हुए हिंदुओं को बाहर निकालने की दिशा में काम किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार मतदान की सफलता का दावा कर रही है और एक नई शुरुआत की आशा व्यक्त कर रही है।

यहां तक कि यूनुस और अंतरिम सरकार के प्रबल समर्थक भी यह दावा नहीं कर सकते कि मतदान किसी भी तरह से निष्पक्ष और नियमित था। रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों को डराने-धमकाने के लिए उन पर हमले किए गए, साथ ही लोगों को मतदान से दूर रखने के लिए देसी बम फेंके गए।

ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हिंदुओं को पीटा गया, जिंदा जलाया गया, भीड़ द्वारा मार डाला गया और यातनाएं देकर हत्या की गई। पाकिस्तान से स्वतन्त्र होने तक, पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले इस क्षेत्र में हिंदू-विरोधी घटनाएं अपेक्षाकृत कम थीं। उस समय लोगों का गुस्सा पाकिस्तानियों की ओर था, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में ब्रिटिशों से भी अधिक कठोर औपनिवेशिक शक्ति की तरह व्यवहार किया था।

हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो मूलत: बांग्लादेशी जनता को भारत द्वारा दिया गया एक उपहार थी, भावनाएं आश्चर्यजनक रूप से भारत-विरोधी हो गईं। स्वतंत्र बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारत-विरोधी रवैया इतने वर्षों में बढ़ता गया।

रिपोर्टों के अनुसार, यह कल्पना करना कठिन है कि बांग्लादेश जल्द ही कानून-व्यवस्था से संचालित देश बन सकेगा और वहां कुछ हद तक स्थिरता स्थापित हो पाएगी। वर्षों के कुप्रबंधन ने प्रशासनिक तंत्र को कमज़ोर कर दिया है और लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं।

देश में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है, जहां अधिकांश आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। नियमित नौकरी पाने वाले कुछ भाग्यशाली लोग भी बढ़ती कीमतों और वस्तुओं की कमी की शिकायत कर रहे हैं। आम लोग लगातार अराजकता और आर्थिक कुप्रबंधन से कराह रहे हैं।

बांग्लादेश में जारी अस्थिरता भारत के लिए एक भयावह स्थिति है, क्योंकि गंभीर आर्थिक गिरावट लोगों को भारत की ओर धकेल रही है। अवैध पलायन पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर रहा है। अब समय आ गया है कि भारत, बांग्लादेश के प्रति अधिक सक्रिय और सशक्त नीति अपनाए, बजाय इसके कि वह वहां की स्थिति के स्वत: स्थिर होने की प्रतीक्षा करे।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908